Newspaper : Denik Jagran
Edition: Ranchi | Date: 19th July, 2019 | Pg. : 09

नौनिहालों को सम्मान, निखर रही शिक्षा में पहचान

वेंच-डेस्क, बिजली, पोशाक ने बच्चों को दिलाया सम्मान, शिक्षा में इनोवेशन से बढ़ी बच्चों की सीखने की क्षमता

समृद्ध हो रहा झारखंड

राज्य ब्यूरो, रांची : गुरुवार सुबह के पौने आठ बजे हैं। रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर के ठीक बगल में एक बड़ी बस्ती है। झुग्गी-झोपड़ियों वाली इस बस्ती के एक-एक घर से बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं। पूरे ड्रेस में। ड्रेस के साथ पैर में जूता-मोजा और कंधे पर टंगा किताबों से भरा बस्ता। आठ बजे तक पास स्थित सरकारी मिडिल स्कूल खचाखच भर जाता है। एक रंग के ड्रेस में बच्चे मनोरम दृश्य बनाते हैं।

झारखंड में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां सरकार, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अभिभावकों के प्रयास से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को निजी स्कूलों की तरह ड्रेस, स्कूलों में बेंच-डेस्क और पंखे की सुविधा मिली तो मान-सम्मान मिला। 2014-15 के पहले महज तीन-चार हजार स्कूलों में ही बेंच-डेस्क थे। अब आपको अधिसंख्य स्कूलों में नीले रंग के नए बेंच-डेस्क मिलेंगे। बिजली भी पहुंच रही है। कई स्कूलों में पंखे भी लग गए हैं तो कई में लग रहे हैं। यह स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की कहानी कह रही है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट ने गरीबी उन्मूलन के 10 सूचकांकों पर झारखंड के बढ़ते कदम की सराहना की है, इनमें एक स्कूली शिक्षा में सुधार का सूचकांक भी शामिल है। कई अन्य रिपोर्ट भी इसे स्कूली शिक्षा में सुधार को सत्यापित करती है।

4600 स्कूलों का हुआ पुनर्गठन

शिक्षा में इनोवेशन के तहत नीति आयोग के निर्देश पर साथ-ई प्रोजेक्ट के तहत 4600 स्कूलों का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन के बाद कराए गए आंतरिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि इससे सात लाख बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावा बेहतर वातावरण मिल रहा है, क्योंकि उन्हें आवश्यक संख्या में शिक्षक व अन्य संसाधन मिलने लगे हैं। 96 फीसद बच्चे इससे संतुष्ट हैं। 4,500 शिक्षकों की जरूरत कम हुई है तथा लगभग 400 करोड़ की बचत हुई है।

बच्चों को काउंसिलिंग कर लाया गया वापस

स्कूलों के विलय के बाद 150 ऐसे स्कूल चिह्नित किए गए थे जहां के बच्चे पुनर्गठित स्कूल में नहीं जा रहे थे। उनके अभिभावकों की काउंसिलिंग कर उन्हें वापस लाया गया। इस प्रयास से 90 फीसद बच्चे वापस आ गए। विलय के कारण स्कूलों की दूरी बढ़ने को देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा छह से सात के छात्र-छात्राओं को साइकिल देने का निर्णय लिया है। शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में साइकिल के अलावा अन्य परिवहन या परिवहन भत्ता का भी विकल्प अपनाया गया है।

रांची के जगन्नाथपुर मध्य विद्यालय में कक्षा शुरू होने से पहले प्रार्थना करते बच्चे● जागरण

दसवीं में ड्रॉप आउट बड़ी चुनौती, 18 फीसद छोड़ देते स्कूल

सरकार ने अपनी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ाने में पिछले दो वित्तीय वर्षों में बड़े पैमाने पर स्कूलों के पुनर्गठन की भूमिका पर जोर दिया है। वहीं, सरकार ने ड्रॉप आउट को बड़ी चुनौती बताया है। हालांकि इसमें भी भारी कमी लाने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है।

2016-17 में ग्रेड दस में स्कूल छोड़नेवाले बच्चों की संख्या 50% थी जो 2017-18 में घटकर 18.72% हो गई। उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। हालांकि इसमें भी काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2010-11 में यह रेशियो 7.5 फीसद ही था जो 2017-18 में बढ़कर 18 फीसद हो गया।

सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूली शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। नीति आयोग के अलावा कई स्तरों पर इसकी सराहना हुई है।
--नीरा यादव, शिक्षा मंत्री

इनमें भी सुधार की जरूरत

	झारखंड	भारत
भौतिकी	18.68	30.64
रसायन विज्ञान	18.68	30.44
जीव विज्ञान	18.16	29.06
कंप्यूटर	19.28	34.68

नोट : आंकड़े प्रतिशत में हैं।

इन पर करना होगा काम

- राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। हालांकि सभी जिलों में नियुक्ति हो रही है।
- प्राथमिक स्कूलों में भी नियुक्ति के बाद भी पद रिक्त हैं।
- प्राथमिक व माध्यमिक दोनों श्रेणी के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के अधिसंख्य पद रिक्त हैं।
- स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की भी नियुक्ति नहीं हुई है।
- बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभी और काम करना होगा।
- सुदूर क्षेत्रों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

शिक्षा से ही खुलेगा विकास का रास्ता

3.8 फीसद बच्चे अब भी विद्यालय से बाहर

बारह साल में आठ बार आधे बच्चे हो गए फेल

जागरण सरोकार

शिक्षा में झारखंड की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी नहीं लेकिन हाल के दिनों में इसके स्तर में बहुत सुधार हुआ है। दैनिक जागरण लगातार समय-समय पर खबरें प्रकाशित कर इस दिशा में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। सुशिक्षित समाज जागरण के सात सरोकारों में सर्वोपरि है।

सीखने की क्षमता में राज्य देश में चौथे स्थान पर

बच्चों की सीखने की क्षमता तथा शिक्षा की गुणवत्ता में झारखंड पूरे देश में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में ये बातें सामने आई हैं। बच्चों के सीखने की क्षमता तथा गुणवत्ता में झारखंड को कुल 180 अंकों में 154 अंक प्राप्त हुआ है। झारखंड के साथ ही केरल और आंध्र प्रदेश को भी इतने अंक मिले हैं। कर्नाटक, चंडीगढ़ तथा राजस्थान ही झारखंड और इन दोनों राज्यों से आगे है।

केस 01 प्राथमिक उर्दू स्कूल नगड़ी तथा नव प्राथमिक स्कूल भागलपुर का विलय मिडिल स्कूल, नगड़ी में किया गया। दोनों स्कूलों में क्रमशः महज 16 और 20 बच्चे ही नामांकित थे। दो-दो वलासरूम तथा एकमात्र शिक्षक थे। विलय के बाद मिडिल स्कूल, नगड़ी में कक्षा एक से आठ तक 650 बच्चे, 27 शिक्षक तथा 18 वलास रूम हो गए हैं। सभी कक्षाओं में विषयवार शिक्षक मिल गए हैं।

केस 02 राज्य सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग तैयारी के लिए आकांक्षा कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत 40 बच्चों को राज्य स्तर पर इसकी तैयारी कराई जाती है। पिछले वर्ष इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों के 20 तथा इस वर्ष 22 बच्चों का जेई मेन्स में अच्छा परसेंटाइल मिला।